ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 6, June 2016

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव

डॉ. प्रकाश चंद मीना

सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़, अलवर

सार

भारत में समय-समय पर अलग-अलग क्षेत्रीय पार्टियों का गठन होता रहा है और ये देश के संसदीय लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाती रही हैं। शिरोमणि अकाली दल और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस जैसी कुछ पार्टियां तो 1947 में देश के आजाद होने से भी पहले गठित हो गई थीं। लेकिन ज्यादातर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां देश के आजाद होने के बाद ही गठित हुई हैं।क्षेत्रीय दलों की श्रेणी में रखी जाने वाली पार्टियों का विकास खास तौर पर 1967 के बाद तेज हुआ, जब देश के स्वतंत्रता संग्राम में खास भूमिका निभाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की देश के मतदाताओं पर पकड़ ढीली होने लगी।इस समय लगभग चार दर्जन राज्य स्तरीय पार्टियों को चुनाव आयोग की मान्यता हासिल है और लगभग दो दर्जन ऐसी हैं जिन्हें अब तक मान्यता नहीं मिली है। इनमें से कई अपने राज्य में सत्ता में हैं तो कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियों ने लोकप्रियता हासिल कर राष्ट्रीय पार्टियों के सामने चुनौती पेश कर दी है। इन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों की ओर से क्षेत्र या राज्य विशेष की राजनीतिक और आर्थिक उपेक्षा को अपना आधार बनाया और आगे बढ़ीं।सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टियों में शामिल शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1920 में धार्मिक संगठन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक सिमिति (एसजीपीसी) ने की ताकि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अविभाजित पंजाब में सिखों की मुख्य प्रतिनिधि बन सके।

परिचय

इस समय क्षेत्रीय पार्टियां आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अपने अकेले दम पर या राष्ट्रीय पार्टी अथवा किसी और पार्टी के साथ मिल कर शासन कर रही हैं।इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों की एक खासियत यह है कि ये सभी एक ऐसे नेता के इशारे पर चलती हैं जिसकी सत्ता को पार्टी के अंदर कोई चुनौती नहीं दे सकता। [1]संक्षेप में कहें तो इन्हें कोई एक नेता और उसके विश्वासपात्र चला रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों का भी पार्टी के काम-काज में खासा दखल रहता है।जो पार्टियां किसी वैचारिक आधार पर गठित हुई हैं, उन्हें भी समय के साथ व्यक्तिगत जागीर और व्यक्तिगत हितों की रक्षा का साधन बना दिया गया है।इसलिए सामान्य तौर पर ऐसी पार्टियों का अस्तित्व भी उनका संचालन करने वाले नेता के जीवन काल से काफी नजदीक से जुड़ा है।क्षेत्रीय संगठनों की एक और खास बात यह है कि परिवार के सदस्य, नजदीकी रिश्तेदार और मित्र पार्टी के काम का संचालन करते हैं और उनमें से ही एक उसके नेता की विरासत को उसके जीवन काल के दौरान या उसके बाद संभाल लेता है।हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी (सपा) के सबसे ताकतवर नेता और उनके बेटे के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष के खुल कर सामने आ जाने की वजह से यह पार्टी चर्चा में है। इसलिए क्षेत्रीय दलों की विडंबना और इनके भविष्य को समझने के लिए सपा को नजदीक से समझना दिलचस्प होगा।देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर सपा का 2012 से शासन है और 1992 में इसके गठन के बाद से यह लगभग एक दशक तक सत्ता में रही है। इसने केंद्र में भी सत्ता में साझेदारी की है।पार्टी का गठन उत्तर प्रदेश के तीन बार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग हो कर किया था। 1990 के दशक की शुरुआत में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद मुलायम का प्रभाव काफी बढ़ा। इससे पहचान की राजनीति को भी खास कर उत्तर भारत में काफी बढ़ावा मिला था।[2]मुलायम 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस पद पर पूरे एक साल और 201 दिन तक रहे। 1991 के आम चुनाव में जनता दल की हार के बाद उन्हें यह कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने सपा की स्थापना की और दो बार मुख्यमंत्री बने।इस साल 22 नवंबर को वे 78 वर्ष के हो जाएंगे और कहा जा रहा है कि अब वे उतने स्वस्थ नहीं रहते। पार्टी के अंदर पिछले कुछ समय से वर्चस्व की लड़ाई कभी खुल कर, तो कभी दबे-छुपे चल ही रही है लेकिन जितना खुल कर यह अब सामने आई है, इतनी कभी नहीं आई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के गुट मुलायम सिंह के बाद के युग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अखिलेश जहां मुलायम के सबसे बड़े बेटे हैं, वहीं शिवपाल उनके छोटे भाई हैं।पार्टी में खुद अपनी सत्ता को चुनौती मिलती देख कर और पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुलायम सिंह ने दखल दिया और एक ऐसा रास्ता दिया जो उनकी नजर में राजनीतिक रूप से उनको प्रासंगिक भी बनाए

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 6, June 2016

रखता और अगले चुनाव में सत्ता बनाए रखने की पार्टी की उम्मीद को भी जिंदा रखता।मुलायम की ओर से पेश किए गए एकजुटता के प्रदर्शन को अखिलेश और सपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल ने जारी रखने से इंकार कर दिया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 25 साल पुरानी पार्टी के सामने इसके अस्तित्व को ले कर गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है। इसमें बहुत सी दरारें आ गई हैं, जिनको मुलायम ढंक रहे हैं।यह समझते हुए कि उनके बेटे के कदम अगले चुनाव में पार्टी की जीत की संभावना को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुलायम ने दखल दिया और शिवपाल का गुस्सा ठंडा करने के लिए अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा कर उन्हें इस पर बिठा दिया। मुख्यमंत्री के लिए यह स्पष्ट संकेत होना चाहिए था, लेकिन अखिलेश माने नहीं और उन्होंने भी शिवपाल और अपने पिता के पसंदीदा मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया।शिवपाल को न सिर्फ राज्य में पार्टी का प्रमुख बना दिया गया, बल्कि मुलायम ने यह भी सुनिश्चित किया कि अखिलेश की ओर से उठाए गए सभी कदम वापस ले लिए जाएं। सपा के शीर्ष पुरुष एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने मुख्यमंत्री को झटका देते हुए अमर सिंह को पार्टी का महासचिव बना दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने 'बाहरी' व्यक्ति बताया था।[3]पार्टी से 2010 में निष्कासित कर दिए गए अमर सिंह को इस वर्ष मई में दुबारा पार्टी में शामिल किया गया था और पार्टी की ओर से राज्य सभा भी भेज दिया गया।यहां यह बताना जरूरी है कि भले ही मुख्य संघर्ष अखिलेश और शिवपाल के बीच चल रहा हो, लेकिन पार्टी में और भी कई ताकतवर गुट हैं जो फिलहाल इनमें से किसी एक पक्ष के साथ खड़े हैं, मगर आने वाले समय में यह देख कर पाला बदल सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है।फिर बारी आती है हाल में पार्टी के महासचिव नियुक्त किए गए अमर सिंह की। इसी तरह राज्य सभा में पार्टी के नेता रामगोपाल यादव हैं, जो पार्टी सुप्रीमो के चचेरे भाई होने के साथ ही पार्टी के ऐसे विचारक भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि हर अहम मुद्दे पर मुलायम उनसे जरूर संपर्क करते हैं। दूसरी तरफ मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता और उनके महत्वाकांक्षी बेटे प्रतीक यादव हैं, जो बड़े स्तर पर जमीन-जायदाद का कारोबार करते हैं। यादव परिवार की आतंरिक लड़ाई में इन सभी के हित दांव पर लगे हैं।जिम्मेवारी संभालने के तुरंत बाद शिवपाल ने तत्तपरता दिखाते हुए अखिलेश से करीबी रखने वाले सात युवा नेताओं को निकाल दिया। इससे पहले उन्होंने एक विधान पार्षद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी जो मुलायम के चचेरे भाई रामगोपाल यादव के नजदीकी रिश्तेदार हैं।बड़ा सवाल यह है कि जो समझौता लादा गया है, वह लंबे समय तक चलेगा या फिर कुछ हफ्तों या महीनों में ही बिखर जाएगा। समझौता लंबा खिचने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सपा के अंदर कई लड़ाइयां चल रही हैं।हालांकि सपा में लड़ाइयां कई महीनों से चल रही हैं, लेकिन अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की वजह से यह लड़ाई खुल कर सामने आ गई है। हो सकता है कि चुनाव फरवरी में ही हो जाएं और इस चुनाव ने ही दोनों खेमों में बेचैनी ला दी है क्योंकि चुनाव से पहले 403 टिकट दाव पर हैं। दोनों गुट को पता है कि मजबूत वही होगा जिसके साथ विधायकों की संख्या और उनकी प्रतिबद्धता होगी।इसलिए अखिलेश और शिवपाल दोनों ही चाहेंगे कि उनके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिल सकें और उनकी खेमेबंदी मजबूत हो सके। दोनों ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने की होड़ में हैं।२०१२ के विधानसभा चुनाव में सपा को पूर्ण बहुमत मिला और अखिलेश को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई। वे साढ़े चार साल से इस पद पर तो हैं, लेकिन उनकी शक्तियां बहुत सीमित हैं और हाथ बंधे हुए हैं।उनके पिता के अलावा भी पार्टी में कम से कम दो और सत्ता केंद्र हैं जो राज्य सरकार में अपनी चलाते हैं। अखिलेश की हालत को देख कर राज्य में यह कहावत चल पड़ी है कि यहां साढ़े तीन मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। मुलायम, शिवपाल और पिछले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले पार्टी में वापस लिए गए आजम खान ये तीन मुख्यमंत्री हैं [4]और आधे मुख्यमंत्री खुद अखिलेश हैं।चुनाव को नजदीक देख कर अखिलेश खास तौर पर इस दाग को छुड़ाना चाहते थे कि वे सिर्फ कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपनी छवि एक ईमानदार और बेहतर नेता के तौर पर पेश की है। वे इस वर्चस्व की लड़ाई में आगे निकलना चाहते थे। वे अब यह संदेश देना चाह रहे थे कि अगर उन्हें खुली छूट दी गई होती तो वे राज्य का और बेहतर विकास कर सकते थे।सीधे-सीधे मुठभेड़ मोल लेते हुए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से अपने पिता के विश्वस्त माने जाने वाले दो मंत्रियों गायत्री प्रजापित और राजकिशोर सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया। इसी तरह उन्होंने तीन महीने पहले बनाए गए शिवपाल के करीबी मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटा दिया और उनकी जगह अपनी पसंद के राहुल प्रसाद भटनागर को यह पद दे दिया। इसके बाद उन्होंने सीधे शिवपाल पर हमला बोल दिया और उनके भी अहम मंत्रालय उनसे छीन लिए।

इससे पहले अखिलेश ने कौमी एकता दल के सपा में विलय को यह कह कर रोक दिया था कि इससे पार्टी की छवि खराब होगी। कौमी एकता दल के मुख्य संरक्षक और वित्तपोषण करने वाले कोई और नहीं बल्कि कुख्ताय अपराधी मुख्तार अंसारी हैं। यह विलय शिवपाल के नेतृत्व में हो रहा था और इसे मुलायम की भी सहमति थी।राज्य में कानून-व्यवस्था की बदहाली के मुद्दे पर विपक्ष के हमले को देखते हुए हाल ही में अखिलेश ने राज्य पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को कह दिया है कि अब अपराध को ले कर 'जीरो टोलरेंस' की नीति अपनाई जाए।मुलायम ने शिवपाल को उत्तर प्रदेश पार्टी का प्रमुख यह सोच कर ही बनाया है कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत तौर पर अच्छी तरह जानते हैं और उनके व अखिलेश के बीच बेहतर कड़ी का काम करेंगे।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 6, June 2016

इसलिए अखिलेश नहीं बल्कि शिवपाल ही टिकट वितरण में मुख्य भूमिका निभाएंगे क्योंकि राजनीतिक जमीनी समझ उन्हीं को है और हर विधानसभा सीट पर जातीय गणित का ध्यान रखने में वे ज्यादा सक्षम हैं।टिकट बंटवारे में अहम भूमिका नहीं मिलने के बाद अखिलेश ने कुछ समय के लिए चुप्पी भले साध ली हो, लेकिन वे ज्यादा समय तक अपमान सहन करने वाले नहीं हैं और सही मौका देख कर पलटवार कर सकते हैं। अखिलेश ही पार्टी का मुख्य चेहरा थे और अब उन्हें ही किनारे किया जा रहा है, ऐसे में पार्टी को सबसे अहम पहचान ही खतरे में है।सपा को वोटरों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है और मुमकिन है कि मुलायम की ओर से अंतिम समय में की गई कोशिशें सत्ता में वापसी के लिए नाकाफी साबित हों।उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना जातीय गणित को साधना तो है ही लेकिन साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है कि आपके बारे में जनता की राय क्या है।सपा जिन चुनौतियों का सामना कर रही है वह कोई अपवाद नहीं है और लगभग यही खतरे उन सभी क्षेत्रीय पार्टियों के ढांचे में ही निहित हैं जो या तो सत्ता में हैं या सत्ता पाने के लिए संघर्षरत हैं।उदाहरण के तौर पर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में चार बार सत्ता में रही और हर बार इसकी एकमात्र सर्व शक्तिमान नेता मायावती मुख्यमंत्री बनीं। पार्टी की स्थापना 1984 में कांशी राम ने इस उद्देश्य के साथ की थी कि बहुजन समाज यानी दलित, आदिवासी,[5] अन्य पिछड़ी जातियां(ओबीसी) और अल्प संख्यकों को सत्ता में बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके।स्वर्गीय कांशी राम ने पूर्व स्कूल अध्यापिका मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उनकी मौत के बाद बसपा का वजूद पूरी तरह मायावती के ऊपर ही टिक गया। उनके नेतृत्व को पार्टी में किसी और नेता की ओर से न तो चुनौती दी जा सकती है न ही कोई सवाल पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के बहुत से दलित उन्हें अपना नेता मानते हैं।

हालांकि पार्टी ने अपने सिद्धांतों की प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार ईवी रामासामी और छत्रपति शाहूजी महराज से हासिल की है, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद मायवती ने अपना लक्ष्य और दर्शन किसी भी तरह सत्ता हासिल करना बना लिया है। वर्षों से अब बसपा को एकजुट रखने वाली ताकत वही हैं। इसलिए अब तो उनके बिना बसपा की कल्पना भी करना नामुमकिन लगता है। जब तक कि वे अपने उत्तराधिकारी को तैयार करना शुरू नहीं कर दें ऐसा लगता है कि उनके सामने नहीं रहने पर पार्टी के तितर-बितर हो जाने में देर नहीं लगेगी। आज के समय में पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनकी अनुपस्थिति में इसे चला सके।इसी तरह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की ही एक और पार्टी राष्ट्रीय लोक दल की बात करें, जिसकी स्थापना पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने 1996 में की थी। राज्य के जाट बहुल जिलों में इसका प्रभाव है। अजीत सिंह को राजनीति की विरासत अपने पिता स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिली, मगर वे सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों सहित विभिन्न पार्टियों से गठबंधन करते रहे हैं ताकि सत्ता में प्रासंगिक बने रहें। अब माना जा रहा है कि उनकी कमान जयंत चौधरी संभालेंगे जो मथुरा से एक बार सांसद भी रहे हैं।पंजाब में शिरोमणि अकाली दल कई बार सत्ता में रही है लेकिन 1970 में जब प्रकाश सिंह बादल चौथे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से पार्टी में पूरी सत्ता उनके परिवार के ही पास केंद्रित हो गई है। भाजपा और अकाली का गठबंधन 2007 से सत्ता में है। प्रकाश सिहं बादल के बेटे राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं।[6]

पड़ोस के राज्य हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलोद) की स्थापना पूर्व उप प्रधान मंत्री और दो बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवी लाल ने अक्तूबर, 1996 में हरियाणा लोक दल के रूप में की जिसका नाम बदल कर 1998 में इनेलोद कर दिया गया। देवी लाल के बेटे ओमप्रकाश चौटाला पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष हैं और चार बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। ओमप्रकाश चौटाला के बेटे अजय सिंह चौटाला पार्टी के महासचिव है।तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीमके) की स्थापना पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अन्नादुरै ने 1949 में की और इसने पहला विधानसभा चुनाव 1967 में जीता। तब से डीएमके में बहुत से बदलाव आए हैं, जिनमें 1972 में हुआ इसका विभाजन भी शामिल है। तब इसके कोषाध्यक्ष और लोकप्रिय फिल्म कलाकार एमजी रामाचंद्रन ने एक नई पार्टी गठित कर ली जिसका नाम था ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (एआइएडीएमके)। इसके बाद से राज्य में यही दो पार्टियां बारी-बारी से सत्ता संभाल रही हैं।

ये पार्टियां काफी हद तक अपने एकमात्र नेता की व्यक्तिगत जागीर में बदल गई हैं। डीएमके का नियंत्रण पांच बार मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि के हाथ में है, जबकि एआईएडीएमके का ये पार्टियां काफी हद तक अपने एकमात्र नेता की व्यक्तिगत जागीर में बदल गई हैं। डीएमके का नियंत्रण पांच बार मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि के हाथ में है, जबकि एआईएडीएमके का नियंत्रण पहले एमजी रामाचंद्रन के हाथ में था और अब उनकी सहकर्मी रहीं जे. जयललिता के हाथ में है। 1987 में एमजी रामाचंद्रन की मृत्यु के बाद से उनकी पार्टी की जिम्मेवारी जयललिता के हाथ में आ गई थी। वे भी पांच बार मुख्यमंत्री रही हैं।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 6, June 2016

हालांकि डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने अनौपचारिक तौर पर अपने छोटे पुत्र एमके स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन आने वाले समय में परिवार में इस बात को ले कर झगड़े की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। खास कर जब इसके सर्वमान्य नेता नहीं रहेंगे।इसी तरह एआइएडीएमके में भी इस पार्टी की सर्वोपरि नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री ज़े. जयललिता के बाद यही समस्या आने वाली है। उन्होंने किसी नेता को अपने उत्तराधिकारी के रूप में भी विकसित नहीं किया है और पार्टी को बहुत कड़े अनुशासन के साथ चलाया है।पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अन्य क्षेत्रीय दलों से अलग नहीं हैं। यह भी एक व्यक्ति द्वारा संचालित होने वाली पार्टी है। ममता का आदेश ही आखिरी फैसला होता है जिस पर पार्टी में कोई मशविरा होने का सवाल तक नहीं है। इस साल की शुरुआत में ममता के प्रभाव की वजह से ही पार्टी राज्य में तीन दशक तक राज करने वाली वामपंथी पार्टियों और भाजपा को पछाड़ कर दुबारा सत्ता में आ सकी है।आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी दो क्षेत्रीय दलों तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का शासन है। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग को ले कर चले आंदोलन से ही 2001 में टीआरएस का जन्म हुआ था। 2014 में हुए राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में यह पार्टी सत्ता में आई और इसके प्रमुख के चंद्रशेखर राव राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। राव पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी।[7]उनके पुत्र के.टी. रामाराव राज्य सरकार में मंत्री हैं और बेटी के कविता लोकसभा सांसद हैं।इसी तरह टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अपने ससुर एन.टी. रामराव के निधन के बाद से उन्होंने ही पार्टी की कमान संभाली है और इस दौरान वे 1995 से 2004 तक मुख्यमंत्री रहे और अब वर्ष 2014 से दुबारा राज्य की कमान संभाल रहे हैं।ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) की स्थापना 1997 में हुई और इसके तीन साल बाद यह पार्टी सत्ता में आ गई, जिसके बाद से यह लगातार सत्ता में है। पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक ने लगातार चार विधानसभा चुनाव जीते हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने तब की भाजपा नेतृत्व वाली अटल बिहारी वाजपेयी की राजग सरकार में केंद्रीय खनन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 2000 का यह चुनाव उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन में ही लड़ा था। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजद ने भाजपा से चुनाव गठजोड़ तोड़ लिया। दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की तरह यहां भी नवीन पटनायक ही सभी फैसले लेते हैं। बीजद भी कई मामलों में दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों से मेल खाती है।जहां ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां व्यक्ति आधारित और एक व्यक्ति या उसके परिवार से संचालित हो रही हैं, इनका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ता का हस्तांतरण नए उत्तराधिकारी को कितनी आसानी से होता है। सत्ता परिवार के जितने ज्यादा सदस्यों के बीच बंटी होगी, पार्टी के बिखरने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मामले में देख रहे हैं।

विचार-विमर्श

भारत में न केवल राष्ट्रीय स्तर की दल हैं बल्कि क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दल भी हैं। 1952 में पहले लोकसभा चुनावों में, चुनाव आयोग ने 25 क्षेत्रीय दलों को मान्यता दी। वर्तमान में, चुनाव आयोग ने 58 क्षेत्रीय दलों को मान्यता दी है।आज महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दल हैं – शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कांफ्रेंस, डी . ऐम. के, अन्ना डी.ऐम.के, तेलुगू देशम, असम गण परिषद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मिजोरम नेशनल फ्रंट, नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, मणिपुर पीपुल्स पार्टी, महाराष्ट्र गोमातक पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम संग्राम परिषद आदि।वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र के लिए दल जरूरी हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश है। इस लिए भारत में राजनीतिक दलों का होना निश्चित है। भारत में बहुत सारे राजनीकित दल मौजूद है। कुछ दल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित हैं जबकि कुछ क्षेत्रीय स्तर तक सीमित हैं।[8] राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के साथ-साथ भारतीय पार्टी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति है। वर्तमान में, भारत में 50 से अधिक क्षेत्रीय दल मौजूद हैं।लेकिन 1991 के लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर, चुनाव आयोग ने 32 क्षेत्रीय दलों को मान्यता दी। अप्रैल-मई 1996 के आम चुनावों के दौरान, चुनाव आयोग ने 400 से अधिक राजनीतिक दलों को पंजीकृत किया।वर्तमान में, चुनाव आयोग ने 58 राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता दी है। क्षेत्रीय स्तर के राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई है। प्रमुख क्षेत्रीय दल शिरोमणि अकाली दल, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम(ADMK), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम(ADMK), तेलुगू देशम, असम गण परिषद, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य क्षेत्रीय दल हैं। भारत में क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व का इतिहास बहुत पुराना है। पंजाब में 1920 से अकाली दल की क्षेत्रीय राजनीति चलती आ रही है। 1949 में, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल का गठन किया गया था। पहला मुस्लिम सम्मेलन कश्मीर में स्थापित किया गया था। आजादी के बाद से क्षेत्रीय दलों की संख्या बहुत बड़ी है। क्षेत्रीय दलों के उदय के मुख्य कारण इस प्रकार हैं।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 6, June 2016

भौगोलिक कारण :

भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसकी भौगोलिक संरचना में अंतर हैं। आजादी के बाद जब राज्यों का फिर से गठन किया गया, तो राज्यों की पुरानी सीमाओं को नहीं भुलाया गया, लेकिन सीमाओं को फिर से बनाने का आधार बनाया गया।इस भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कुछ क्षेत्रों को देश के अन्य क्षेत्रों से अलग कर दिया गया। परिणामस्वरूप, एक राज्य में रहने वाले लोगों में एकता की भावना नहीं उत्पन्न हो सकी । परिणामस्वरूप , जो राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग हो गए, वहां क्षेत्रीय दलों का उदय होना स्वाभाविक था। जैसे हिल्स पीपुल्स यूनियन और सिक्किम संग्राम परिषद जैसे दलों के उदय के लिए भौगोलिक कारक ही जिम्मेदार हैं।

जातिवाद :

भारत में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का गठन जाति के आधार पर हुआ है। कई नेताओं का उदय और पतन जाति के कारण हुआ है। क्योंकि भारत में विभिन्न जातियों और उप-जातियों के लोगों का निवास है।परिणामस्वरूप, कई नेता, जातिगत समर्थन के आधार पर,अपने को महत्व को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय दलों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में डी.ऐम.के.(D.M.K.) और अन्ना डी.ऐम.के.(A.D.M.K.) ब्राह्मण या गैर-ब्राह्मण समूह हैं। बहुजन समाज पार्टी का आधार जातिवाद है।[9]

धर्म :

क्षेत्रीय दलों के गठन में धर्म भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जब किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष धर्म के लोग बड़ी संख्या में ईर्ष्या करते हैं, तो राजनीतिक आकांक्षाएं आसानी से उनमें विकसित हो सकती हैं। यह समर्थन के आधार पर है कि कई लोग अपने स्थायी महत्व को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय दलों का गठन करते हैं। जैसे तमिलनाडु डी.ऐम.के.और अन्ना डी.ऐम.के. गैर – ब्राह्मणी दल हैं।

भाषा :

जातिवाद और वर्ग की तरह, भाषा ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में कई भाषाएँ बोली जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, 22 भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है।

लेकिन भाषा के मतभेदों ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। भारत में क्षेत्रवाद से जुड़े कई सवाल भाषा विवाद के इर्द-गिर्द घूमते हैं। नॉर्मन डी. पाल्मर (Norman D.Palmar) के अनुसार, “भारत की अधिकांश क्षेत्रीय राजनीति भाषा के सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है।” एक भाषा बोलने वाले लोगों में क्षेत्रीय भावनाओं को विकसित करने की शक्ति है।

परिणाम

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के विकास में इन भावनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में, भाषाई रचनाओं ने तेलुगू देशम जैसी पार्टी के विकास में बहुत योगदान दिया है।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 6, June 2016

ऐतिहासिक कारण :

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय में इतिहास का दोहरा सहयोग रहा है- सकारात्मक और नकारात्मक। शिवसेना को सकारात्मक योगदान और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नकारात्मक योगदान के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का कहना है कि प्राचीन काल से ही उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों पर शासन किया है।[10]

आर्थिक कारण :

क्षेत्रीय दलों के उदय में आर्थिक कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने जिस तरह से विकास किया है, उसमें बहुत असमानता है। कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हुए हैं और कुछ क्षेत्र कम विकसित हुए हैं।इसका कारण यह है कि सत्ता में रहने वालों ने अपने क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने अपने संसाधनों के विकास पर अधिक ध्यान दिया। इसलिए, इन सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीयता की भावना जागृत हुई और परिणामस्वरूप क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ।

राजनीतिक कारण :

राजनेताओं ने क्षेत्रीय दलों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे कई राजनेता हैं जिनके पास सत्ता नहीं है, वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने स्वार्थों के लिए क्षेत्रीय भावनाओं का उपयोग करते हैं।इसके अलावा, राजनीतिक दलों के आंतरिक शक्ति संघर्ष के कारण, पार्टी के नेता अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय भावनाओं का उपयोग करते हैं। परिणामस्वरूप, कई राजनेता अपनी राजनीतिक महत्वकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय दलों का गठन करते हैं।

कांग्रेस पार्टी में आंतरिक सत्ता संघर्ष ने कई क्षेत्रीय दलों को आधार बनाया। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में बंगाली कांग्रेस, केरल में केरल कांग्रेस, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, तमिलनाडु में तमिल मनीला कांग्रेस और ओडिशा में उत्कल कांग्रेस का उदय राजनीतिक कारणों से हुआ है। उपरोक्त कारणों ने क्षेत्रीय दलों के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्षेत्रीय दलों के उदय ने राजनीतिक और चरमपंथी प्रवृत्ति को जन्म दिया है। कहीं न कहीं ये क्षेत्रीय दल अलग-अलग राज्यों की मांग करने लगे हैं।इससे भारत की एकता और अखंडता को गंभीर खतरा है। इसलिए, अधिक राज्यों का निर्माण करके, लेकिन देश के विभिन्न क्षेत्रों में उचित सुविधाएँ प्रदान करके इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। उदहारण के लिए हमने निचे कुछ छेत्रिय राजनीति दलों के बारे में बताया है।

शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) :

अकाली दल एक क्षेत्रीय है यह पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पार्टी का चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ महत्व है, लेकिन पंजाब में इसकी स्थिति मजबूत है, मुख्य रूप से सिखों के प्रतिनिधि निकाय के रूप में।[11]

अकाली दल का इतिहास:

अकाली दल उन कुछ दलों में से एक है जिसका गठन आजादी से पहले हुआ था। वास्तव में, पार्टी का गठन राजनीतिक उद्देश्यों के बजाय धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य गुरुद्वारे की पवित्रता को बनाए रखना था।1925 से पहले, गुरुद्वारों का प्रबंधन महंतों द्वारा किया जाता था और महंतों ने गुरुद्वारों को विलासिता का अड्डा बना रखा था। इसे सुधारने के लिए सिख धर्म का गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चलाया गया।सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की और वर्तमान सिखों को जेल में

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 6, June 2016

डाल दिया गया, लेकिन अंत में पंजाब सरकार ने गुरुद्वारों का प्रबंधन करने के लिए कानून द्वारा एक शिरोमणि परबन्दक समिति की स्थापना की, जिससे अकाली दल को राजनीतिक मान्यता मिली। इस पार्टी के मुख्य नेता मास्टर तारा सिंह और बाबा खड़क सिंह थे। अकाली दल ने देश को स्वतंत्र बनाने में कांग्रेस का पूरा समर्थन किया।आजादी के बाद, अकाली दल कांग्रेस की कई गतिविधियों से असंतुष्ट रहा, जिसके कारण 1948 में मास्टर तारा सिंह ने कहा कि अकाली दल का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। 1952 के आम चुनाव अकाली दल द्वारा स्वतंत्र रूप से लड़े गए और एक बड़ी सफलता थी।अकाली दल ने सिखों के हित में एक पंजाबी राज्य को अपना लक्ष्य बनाने की माँग की। मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में, अकाली दल ने एक पंजाबी राज्य की मांग को पूरा करने के लिए न्यायिक आंदोलन चलाया।

निष्कर्ष

अकाली दल का संगठन :

2 सितंबर 1974 को अकाली दल के संगठन से संबंधित निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए हैं-गाँव, कस्बे या कस्बे में जत्था स्थापित करने के लिए कम से कम 10 सदस्य होना आवश्यक है। गाँव, कस्बे या कस्बे आदि में केवल एक ही जत्था हो सकता है।जिस सर्कल में कम से कम 5 जत्थे बनते हैं या 100 से अधिक सदस्य भर्ती किए जाते हैं, एक सर्कल जत्था स्थापित किया जाएगा।सरकार अपने प्रतिनिधियों को जत्था जिला अकाली दल को चुनेगी और भेजेगी। यदि सर्किल जठिया स्थापित करने की जगह पर 100 से अधिक सदस्यों की भर्ती की जाती है, तो शिरोमणि अकाली दल के अनुमोदन से जिला अकाली जत्था का गठन किया जाएगा।ग्राम अकाली जत्थे सर्किल जत्थे के लिए सदस्यों का चयन करेंगे, सर्कल अकाली जत्था के सदस्य जिला अकाली जत्था के सर्कल सदस्यों का चयन करेंगे और भेजेंगे।[12]

अकाली दल के विभिन्न संगठनों का चुनाव :

2 सितंबर, 1974 को अकाली दल की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित कानून में, अकाली दल के विभिन्न संगठनों के चुनावों के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए थे।शिरोमणि अकाली दल का आयोजन गाँव के आधार पर किया जाता है। जत्था गाँव के 10 सदस्यों में से एक सदस्य सर्किल अकाली जत्था का एक साधारण सदस्य चुना जाता है। सर्कल अकाली जत्था के 50 सदस्यों में से एक सदस्य जिला अकाली जत्था के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है। प्रत्येक जत्थे को शिरोमणि अकाली दल की सामान्य समिति के लिए एक निश्चित संख्या में प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार है।

अकाली दल का विभाजन:

अकाली दल लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा था। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप, 20 अगस्त, 1980 को अकाली दल अलग हो गया। अकाली दल (तलवंडी) और अकाली दल (संत लोंगोवाल)। अकाली दल (लोंगोवाल) को अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त था।17 मई 1981 को अमृतसर में पार्टी का एक प्रतिनिधि सत्र आयोजित किया गया, जिसमें संत लोंगोवाल को सर्वसम्मति से अकाली दल का अध्यक्ष चुना गया। अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि अकाली दल का राजनीतिक उद्देश्य आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और 1978 की लुधियाना अकाली कांग्रेस को लागू करना था।अकाली दल ने मांग की कि अमृतसर को एक पवित्र शहर का दर्जा दिया जाए और वहां नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। गुटबाजी के कारण अकाली दल कई गुटों में बंट गया। 1 मई, 1994 को अकाली दल (पंथिक), अकाली दल (काबुल), अकाली दल (मान) बब्बर अकाली दल (मंजीत ग्रुप) और अकाली दल (तलवंडी) के साथ मिलकर अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार के साथ मिलकर एक नई पार्टी, अकाली दल (अमृतसर) बनाई गई।अकाली दल (बादल) ने नई पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने सिखों के लिए एक स्वतंत्र मातृभूमि की मांग की है जहां सिखों के प्रसार में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है।मंजीत सिंह के प्रयासों से, अकाल तख्त, अकाली दल (बादल) और अकाली दल (अमृतसर) के अभिनय जत्थेदार का अप्रैल 1995 में विलय हो गया और शिरोमणि अकाली दल का गठन हुआ। प्रकाश सिंह बादल को इसका अधीक्षक बनाया गया।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 6, June 2016

अकाली दल का कार्यक्रम और नीतियां :

पंजाब विधानसभा चुनावों के अवसर पर, जनवरी 1977 में, अकाली दल के नेता सरदार सुरजीत सिंह बरनाला ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणापत्र में कहा गया है कि पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज के लिए प्रतिबद्ध है जैसा कि गुरु गोविंद सिंह ने कल्पना की थी। अकाली दल ने राज्य में एक ऐसी सरकार देने का वादा किया है जो लोगों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय प्रदान करेगी।शिरोमणि अकाली दल ने फरवरी, 2015 में पंजाब विधानसभा चुनाव के अवसर पर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसके मुख्य वादे इस प्रकार हैं।पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई अड्डा बनाया जाएगा।पंजाब की सभी सड़कों और गलियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।व्यापारियों को 20 मिलियन के टर्नओवर वाले खाता बही को रखने की आवश्यकता नहीं है।अगले पांच वर्षों में रोजगार के 20 लाख अवसर सृजित होंगे। [13]

अकाली दल की सरकार-

अप्रैल-मई 1996 के आम चुनावों में, अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और उनके गठबंधन ने 13 में से 11 सीटें जीतीं। 16 मई, 1996 को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई और अकाली दल ने भाजपा सरकार का समर्थन किया।फरवरी 1997 में, पंजाब राज्य विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में, अकाली दल बादल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक सफलता हासिल की। गठबंधन नेता सरदार प्रकाश सिंह बादल राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1998 के 12 वें लोकसभा चुनाव में, शिरोमणि अकाली दल ने 8 सीटें जीतीं। किसी अन्य अकाली दल गुट को कोई सफलता नहीं मिली। एक स्थान पर, अकाली दल के समर्थन से एक स्वतंत्र उम्मीदवार जीता।जनता दल के नेता इंद्र कुमार गुजराल ने जालंधर सीट अकाली दल के समर्थन से जीती। शिरोमणि अकाली दल ने 12 वीं लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का समर्थन किया और मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 1999 में हुए 13 वें लोकसभा चुनावों में अकाली दल ने 2 सीटें जीतीं। फरवरी 2002 के पंजाब विधानसभा चुनाव में, अकाली दल ने 41 सीटें जीतीं। अप्रैल-मई 2004 में हुए 14 वें लोकसभा चुनावों में, अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक के रूप में चुनाव लड़ा और पंजाब की 13 में से 8 सीटें जीतीं।फरवरी 2007 के पंजाब विधानसभा चुनावों में, अकाली दल ने 48 सीटें जीतीं। अकाली दल-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 67 सीटें जीतीं। इस गठबंधन के नेता सरदार प्रकाश सिंह बादल को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।2012 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल ने 56 सीटें जीती थीं। सरकार और भाजपा नेता सरकार प्रकाश सिंह बादल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। अप्रैल-मई 2014 में हुए 16 वें लोकसभा चुनावों में दल ने 4 सीटें जीतीं। फरवरी 2015 के पंजाब विधानसभा चुनाव में दल ने केवल 15 सीटें जीतीं।[13]

संदर्भ

1) https://web.archive.org/web/20151201545922/https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/6-national-parties-earned-rs-1200-crore-in-fy18/articleshow/67137504.cms
2) https://web.archive.org/web/20151015054543/https://adrindia.org/content/analysis-income-expenditure-national-political-parties-fy-2015-2015
3) सुब्रत के. मित्र तथा वी.बी. सिंह. 1999.भारत में लोकतंत्र व सामाजिक परिवर्तन : राष्ट्रीय मतदाताओं का एक गहन विश्लेषण. नई दिल्ली: सेज प्रकाशन. ISBN 81-7036-809-X (India HB) ISBN 0-7619-9344-4 (U.S. HB).
4) सुब्रत के. मित्र, माइक एन्स्कट, क्लेमेंस स्पिएस (eds.). 2004. दक्षिण एशिया में राजनीतिक dal. ग्रीनवुड: प्रेजेर.
5) ^http://search.eci.gov.in/eresults/parties/indexSPOS.htm
6) भारत में मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की सूची
7) राजनीतिक दलों की सूची क्रमवार नाम से पार्टियों को ब्राउज करने के लिए
8) राजनीतिक दलों की सूची देश वार पार्टियों को ब्राउज करने के लिए
9) राजनीतिक दलों की विचारधारा की सूची क्रमवार नाम से पार्टियों को ब्राउज करने के लिए

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 6, June 2016

10) अंतरराष्ट्रीय दलों की सदस्यता अंतरराष्ट्रीय दलों द्वारा की गयी सदस्यता के लिए ब्राउज़ करें
11) भारत में उदारवाद
12) भारतीय व्यापार संगठन
13) भारतीय छात्र संगठनों की सूची